



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २१] नई दिल्ली, शनिवार, मई २३, १९९८ (ज्येष्ठ २, १९२०)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1998 (JYAISTHA 2, 1920)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—पृष्ठ 1—	पृष्ठ	भाग II—पृष्ठ 3—	पृष्ठ
(भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम व्यायालयों द्वारा जारी की गई विधिवालियों, विनियमों, आदेशों तथा संकेतनों से संबंधित प्रविष्टुताएँ)		उच्चतम (iii) — भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें द्वारा संतानत भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ सामिल संगठनों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामाजिक विधानों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामाजिक स्वल्प की उपविधियों भी शामिल है) के हिस्से प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राज्यों के खण्ड ३ या खण्ड ५ में प्रकाशित होते हैं) *	
भाग I—पृष्ठ 2—(राजा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम व्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी विधिवालियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लुट्रियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएँ	375		
भाग I—पृष्ठ 3—राजा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकेतनों और सांविधिक आदेशों के संबंध में प्रसिद्ध सूचनाएँ	439	भाग II—पृष्ठ 4—राजा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक विधान और आदेश	*
भाग I—पृष्ठ 4—राजा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी विधिवालियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, लुट्रियों आदि के संबंध में प्रविष्टुताएँ	1	भाग III—पृष्ठ 1—संघ व्यायालयों, नियंत्रक और अहोलेश-परीक्षक, संघ सांकेतिक समिति, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई प्रविष्टुताएँ	489
भाग II—पृष्ठ 1—विधिविधान, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—पृष्ठ 2—प्रैटेंट व्यायालय द्वारा जारी की गई प्रैटेंटों और डिजाइनों से संबंधित प्रविष्टुताएँ और नोटिस	673
भाग II—पृष्ठ 1—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिन तथा रिपोर्ट	*	भाग III—पृष्ठ 3—प्रैटेंट व्यायालयों के प्राधिकार के बहील प्रवाह द्वारा जारी की गई प्रविष्टुताएँ	*
भाग II—पृष्ठ 3—उप-पृष्ठ (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (राजा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ सामिल संगठनों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामाजिक धूमित्यक विधान (जिनमें सामाजिक स्वल्प के प्रावेश और उपविधियां प्रावि भी शामिल हैं)।	*	भाग III—पृष्ठ 4—विधेय अधिष्ठाताएँ जिनमें सांविधिक नियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ, आदेश, विभाग और नोटिस शामिल हैं।	1598
भाग II—पृष्ठ 3—उप-पृष्ठ (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (राजा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ सामिल संगठनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए विधिवालियों और प्रसिद्ध सूचनाएँ	*	भाग IV—वैरास्तकारी अन्तर्वर्ती और नई-सरकारी नियमों द्वारा भारा किए गए विभाग और नोटिस	103
	*	भाग V—ब्रोडे और ड्यूटी दरों में जग्य आदि पर्याप्त के प्राप्ति द्वारा अन्तर्वर्ती	*

## CONTENTS

PAGE	PAGE				
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .</b>	<b>375</b>	<b>PART II—SECTION 3—Sub-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .</b>	<b>439</b>	<b>PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .</b>	<b>439</b>	<b>PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .</b>	<b>745</b>	<b>PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .</b>	<b>489</b>
<b>PART I—SECTION 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .</b>	<b>489</b>	<b>PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .</b>	<b>673</b>	<b>PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .</b>	<b>1599</b>
<b>PART II—SECTION 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .</b>	<b>103</b>	<b>PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .</b>	<b>103</b>	<b>PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .</b>	<b>103</b>

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं।

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सामने गंगालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1998

संकल्प

सं. 1(11)97-खान 6—भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो ग्रेनाइट विकास परिषद के समग्र भारतीय तथा पर्यावरण में कार्य करेगी। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. प्रधान सचिव  
खनन और भूविज्ञान विभाग,  
आंध्र प्रदेश

समस्य

2. सचिव, खनन और भूविज्ञान,  
कर्नाटक सरकार
3. सचिव, खनन और भूविज्ञान,  
उड़ीसा सरकार
4. सचिव, खनन और भूविज्ञान,  
राजस्थान सरकार
5. सचिव, खनन और भूविज्ञान,  
तमिलनाडु सरकार
6. महासचिव, एफ.आर.एम.आरै
7. अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्रेनाइट एवं  
पत्थर एसोसिएशन
8. संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

9. सो.बी.डी.टी. से संयुक्त सचिव स्तर  
का प्रतिनिधि

10. सो.बी.इ.सी. से संयुक्त सचिव स्तर  
का प्रतिनिधि

11. संयुक्त सचिव (एम.पी.),  
खान गंगालय

सक्षम-सचिव

12. निदेशक (एन),  
खान गंगालय

विशेषज्ञ समिति के विचारणीय विषय नीचे लिखे अनुसार होंगे :—

1. ग्रेनाइट के विभिन्न ग्रेडों पर रायलटी की दरों की जांच करना तथा देश में ग्रेनाइट उद्योग के सम्बन्ध विकास के लिए यहां स्तर पर एकरूपता सुझाना।

2. विभिन्न राज्यों में ग्रेनाइट रर डॉड रेन्ट की दरों की जांच करना तथा ग्रेनाइट उद्योग के विकास के लिए वृहद स्तर पर एकरूपता सुझाना।

3. ग्रेनाइट पर कराधान व्यवस्था की जांच करना तथा ग्रेनाइट के विकास तथा नियंत्रित के विकास के लिए उपाय सुझाना।

इस विशेषज्ञ समिति का कार्य-काल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष होगा।

हर प्रतिनिधि  
विवर सचिव

MINISTRY OF MINES  
New Delhi, the 27th April 1998

## RESOLUTION

No. J (11) 97-M-VI.—Government of India have decided to constitute an Expert Committee which will work under the overall guidance and supervision of the Granite Development Council with the following composition :

Chairman

1. Principal Secretary,  
Mining & Geology Deptt.  
Andhra Pradesh.

## Members

2. Secretary,  
Mining & Geology,  
Govt. of Karnataka.
3. Secretary,  
Mining & Geology,  
Govt. of Orissa.
4. Secretary,  
Mining & Geology,  
Govt. of Rajasthan.
5. Secretary,  
Mining & Geology,  
Govt. of Tamil Nadu.
6. Secretary General,  
FIMI.
7. President,  
All India Granite & Stone Association.

8. Joint Secretary,  
M/O Commerce.
9. Joint Secretary,  
Level representative from CBDT.
10. Joint Secretary,  
Level representative from CBRC.
11. Joint Secretary (SP),  
Ministry of Mines.

Member Secretary

12. Director (N),  
Ministry of Mines.

Terms of Reference of the Expert Committee will be as under :—

1. To Examine rates of Royalty on different grades of granite and to suggest some broad uniformity for overall development of the granite industry in the country.
2. To Examine rates of Dead Rent on Granite in different States and to suggest some broad uniformity for the development of granite industry.
3. To Examine the taxation regime on granite and to suggest measures for development and exports of granite.

The tenure of the Expert Committee will be for a period of two years from the date of issuance of this Resolution.

ROOP NARAYAN  
Under Secy.